(c) the number proposed to be purchased in current year and the prices at which proposed to be purchased ?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) :

(a)	1975—76	1976—77	1977—78
No. of Ships acquired	20	8	8
Total D.W.T. (In lakh tonnes)	11·29	2·46	2·62
Total contract price (Rs. in crores)	228·22	61·90	100·94
Countries from where purchased.	GDR, Romania, Yugoslavia U.S.S.R U.K Japan Spain Poland West Germany Taiwan	Yugoslavia U.K. Liberia Romania	GDR Yugoslavia Japan

(b) These ships were acquired after obtaining valuation from international valuers. These provided guidelines for negotiating purchases of ships. The price would depend not only on the size of a vessel but on the gear provided on board as also any special requirement to be met. Generally, the price of vessels obtainable from Far Eastern Yards are cheaper than those obtainable from West and East European Yards.

(c) There are 26 ships on order by Public Sector Shipping Companies at various Shipyards in India and abroad. Out of 9 ships scheduled for delivery during 1978-79 at a total contract price of about Rs. 154·71 crores, two ships have already been delivered and the remaining 7 ships are scheduled to be delivered by 31st March, 1979.

Decentralisation in Planning

2457. SHRI A. BALA PAJANOR : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have evolved a clear and foolproof policy regarding decentralisation in Planning ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the scope and extent of the powers of the Panchayat under the policy and the time-limit by which this will be fully implemented ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Planning Commission is considering the possible decentralisation of planning decisions in relation to the Five Year Plan, 1978-83.

(b) The most important aspect of decentralisation will be the preparation of comperehensive plans for economic development at the Block level. Reports of Working Groups dealing with block-level planning and the role of voluntary bodies in the preparation and implementation of such plans are at present, being examined.

(c) The question of revitalisation of Panchayati Raj Bodies and their effective involvement in the process of plan formulation and implementation is being looked into by a Committee headed by Shri Asoka Mehta. The Committee is likely to submit its report by the end of August, 1978. Concrete policy proposals regarding the scope and extent of powers of the Panchayats will be formulated after the Committee's recommendations become available.

छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन

2458. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े समाचार पत्रों की तुलना में छोटे समाचार पत्रों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए क्या संवर्धनात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में आगामी वर्ष के लिए सरकार की क्या योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्तमान प्रोत्साहनों को चालू रखने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी वार्षिक नीति तैयार करते समय छोटे समाचार-पत्रों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े समाचारपत्रों की तुलना में छोटे समाचार-पत्रों का प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक कदम :—

1. 300 टन तक की हकदारी वाले छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को अपने कोटा का कितना भी हिस्सा नेपा अखबारी कागज, जो आयातित अखबारी कागज से सस्ता है, में लेने की अनुमति है ।

2. कनाडा से हाई सी बिक्री पर अखबारी कागज के आयात के लिए एक बार में 25 मीट्रिक टन की सीमा घटा कर 10 मीट्रिक टन कर दी गई है । इस से काफी संख्या में छोटे समाचार पत्र हाई सी बिक्री की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

3. नई विज्ञापन नीति में, विज्ञापन दरों में, छोटे और मझोले दर्जे के समाचार-पत्रों को उपलक्ष धन (वेटेज) दिया जाता है । भाषायी समाचार-पत्रों को 15 प्रतिशत का अतिरिक्त उपलक्ष धन (वेटेज) दिया जाता है ।

4. सरकारी विज्ञापनों को जारी करने में छोटे समाचारपत्रों के प्रति विशेष उदारता बरती जाती है ; सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों में छोटे दर्जे के समाचारपत्रों का बाहुल्य है ।

5. छोटे समाचारपत्रों को यथा मूल्य एक प्रतिशत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है ।

6. छोटे समाचारपत्रों के लिए समाचार सामग्री उपलब्ध करने की दृष्टि से हिन्दी में "ग्रामीण पत्र सेवा" नामक एक साप्ताहिक सेवा 1977 में आरंभ की गई थी ।

7. हिन्दी और उर्दू में 'यूनेस्को फीचर सेवा' नामक एक अन्य समाचार सेवा 1977 में प्रारंभ की गई थी । यह सेवा इन भाषाओं के पत्रों को यनेस्को के लेखों के हिन्दी और उर्दू के मानक रूपान्तर उपलब्ध करती है जो छोटे समाचारपत्रों के लिए बहुत लाभदायक है ।

Setting up of Ancillary Industries in Rural Areas

2459. SHRI P. KANNAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the moves of industrialists to set up ancillary industries in rural areas to promote rural development ;

(b) whether Government have made an in depth study projected moves of the industrialists and given a sense of direction so that the activities may be co-ordinated and may result in a meaningful impact ; and

(c) the quantification of the efforts of the industrialists made so far during last two years ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) to (c). The proposals of industrialists